

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- ✓ 1. अपील संख्या – 705 / 2013 / जोधपुर
2. अपील संख्या – 706 / 2013 / जोधपुर
3. अपील संख्या – 707 / 2013 / जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, जोधपुरअपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मोहनोत स्टेनलेस स्टील इण्डस्ट्रीज,
हैवी इण्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर.प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री राजेन्द्र जैन, अधिकृत प्रतिनिधि

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17/04/2013

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उक्त तीनो अपीले उपायुक्त (अपीलार्थी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या क्रमशः 37, 38 व 39/सीएसटी/जेयूसी/12-13 पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 31.12.2012 के विरुद्ध पेश की गयी अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 की प्रथम, द्वितीय व तृतीय तिमाहों के लिये पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 29.3.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः आदेश पारित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं।

2. इन तीनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से तीनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की गूल प्रति तीनों अपीलों में पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी अपीलार्थी को वेट अधिनियम की धारा 17(2) के प्रावधान सपटित केन्द्रीय वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) के प्रावधानों के अधीन आयुक्त, वाणिज्यिक कर राजस्थान द्वारा स्टेनलेस स्टील पट्टी/पट्टी के विनिर्माताओं को समयपूर्व प्रतिदाय जारी करने के निर्देशों/आदेशों क्रमांक एफ.16(327)टैक्स/वेट/सीसीटी/06/1937 दिनांक 16.12.2006



लगातार.....

अनुसरण में आवश्यक जांच उपरान्त एवं प्रथम बिन्दु पर कर जमा के सत्यापन के पश्चात आलौच्य अवधि दिनांक 1.4.2009 से 30.6.2009 के लिये प्रतिदाय राशि रूपये 3,23,165/- दिनांक 21.7.2010 को जारी की गयी। इसी प्रकार आलौच्य अवधि दिनांक 1.10.2009 से 31.12.2009 के लिये प्रतिदाय राशि रूपये 7,77,322/- दिनांक 12.01.2011 को जारी की गई। आलौच्य अवधि 1.7.2009 से 30.9.2009 से सम्बन्धित रिकॉर्ड कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

4. उपरोक्त तीनों त्रैमासों के समयपूर्व प्रतिदाय दिये जाने के पश्चात महाराष्ट्र राज्य से यह संसूचित होने पर कि उनके राज्य में पंजीकृत व्यवहारियों के द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र 'सी' केन्द्रीय विद्वी कर अभिनियम की धारा 8(4) के प्रयोजनार्थ अमान्य/अप्रमाणिक हैं। क्योंकि उनका पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है। समयपूर्व दे दिये गये प्रतिदाय में से उन संव्यवहारों से सम्बन्धित जिनका कि पंजीकरण निरस्त हो चुका था तथा कर की गणना रियायती दर पर करते हुए प्रतिदाय दिया जा चुका था, को प्रतिदाय की राशि कम करते हुए अधिक त्रुटिपूर्ण दिये जा चुके प्रतिदाय की वसूली की मांग निकाली गई है।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा अन्तर्राज्यीय संव्यवहार के सन्दर्भ में फर्जी 'सी' फॉर्म प्रस्तुत किये गये, जो कि जांच में मिथ्या पाये गये। महाराष्ट्र राज्य द्वारा विक्रेता व्यवहारियों के पंजीयन निरस्त कर दिये जाने के कारण 'सी' फॉर्म जारी करने हेतु अधिकृत नहीं थे। प्रत्यर्थी द्वारा अमान्य/अप्रमाणिक 'सी' फॉर्म के जरिये रियायती दर से माल विक्रय किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर व ब्याज का आरोपण उचित प्रकार किया गया जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील में स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय अधिकारी को आदेश का समर्थन करते हुए एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपक्षीय द्वारा अपील संख्या 2288-2292/2012/जोधपुर एवं 262-264/2012/जोधपुर में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 18.03.2014 का हवाला देते हुए राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।



लगातार.....

8. प्रकरण के तथ्यों के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 139 एस.टी.सी. 329 (एस.सी.) इण्डिया एजेंसीज (रजि.) बनाम अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर बंगलोर के पैरा 15 में निम्न व्यवस्था की गयी है :-

"The very purpose of prescribing the filing of C forms is that there should not be suppression of any inter-State sales by a selling dealer and evasion of tax to the State from where the actual sales are effected. Secondly, the purchasing dealer also cannot suppress such purchases once he issues C form to the selling dealer. Since the dealer should issue C form has to maintain a detailed account of such C forms obtained from the department prescribed under the States taxation law. The C form is a declaration to be issued only by the sales tax authorities of concerned States. By issuing declaration in C form the purchasing dealer would be benefited as he is entitled to purchase goods by paying only concessional rate of tax of 4 per cent as prescribed by the concerned State of purchasing dealer otherwise the purchasing dealer has to pay tax at a higher rate besides additional taxes on such sales effected within the State where selling dealer is situated."

9. माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स सुरेश ट्रेडिंग कम्पनी (1998) 100 एस.टी.सी. 439 के तथ्यों से हस्तगत प्रकरण में भिन्नता है कि वहां करारों पर करारोपण करने का बिन्दु विवादित था। हस्तगत प्रकरण में समरूप दिये जा चुके प्रतिदाय में से उन संव्यवहारों पर जो कि 'सी' फॉर्म के व्यवहारी के राज्य द्वारा अवैध घोषित किये जा चुके थे, पर प्रतिदाय की राशि कम करने का बिन्दु निहित है।

10. इसी प्रकार माननीय केरल उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2011) 28 वी.एस.टी. 82 (केरल) के आदिकअली बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

"(iii) That what is contemplated in sub-rule (3)(i) of rule 47 of the Rules was only a cross verification if found necessary, for the satisfaction of the assessing authority, with respect to genuineness of the claim or genuineness of the document produced in support. The assessing authority would not be justified in insisting on production of additional proof for the purpose of such verification. If the dealer had already discharged his initial burden cast upon him by virtue of rule 47(2). It was for the assessing authority to conduct "such enquiry as it considers necessary". Any such enquiry, which is basically in the nature of a cross verification was the duty cast upon the assessing authority. The dealer's initial burden of proving entitlement for refund should be presumed discharged, on his production of materials which clearly indicate



लगातार.....

payment of input tax. Thus the rejection of the claim for refund was liable to be quashed and the Commercial Tax Officer was to take up the refund application on file and after making verifications and enquiries if found necessary, pass final orders refunding unadjusted input tax allowable."

11. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 27 (Refund) का अवलोकन किया जाना जाना भी समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

27. Refund.

(1) (a) Subject to the provisions of sub-section (2) of section 53 and section 54, where the assessing authority or the authorized officer after having verified deposits, is satisfied that the payment made by a dealer or a person is in excess of any tax, penalty, interest or other sum due, as a result of an assessment made or in pursuance of an order passed by any competent officer, authority or court, such assessing authority or authorized officer, either *suo moto* or on an application made in this behalf in Form VAT-20 or VAT-21 or VAT-22 as the case may be, shall pass an order for refund, and shall issue a refund order in Form VAT-23A within fifteen days of the order for refund directing the bank, as may be specified by the Commissioner, to transfer the amount of refund into the account of the dealer mentioned in the said Form and shall send a copy thereof to the Treasury Officer or Sub-Treasury Officer as may be directed by the Commissioner. However, where details of bank of the dealer or the person are not available on the record, the refund order shall be issued in Form VAT-23, within fifteen days of the order for refund, along with an advice to the Treasury Officer or Sub-Treasury Officer or the Manager of the Bank authorized to receive money on behalf of the State Government, in Form VAT-24.

(aa) Where the refund of tax, demand or other sum has been made electronically, the authorized bank shall forward a statement of such refunds, on the same day, in part-B of Form VAT-45A to the concerned treasury of the State and a copy of such statement shall be forwarded to the Accountant General Rajasthan.

(b) Where a dealer desires the adjustment of the refund to be made under sub-clause (a), against any amount payable by him, the assessing authority or the authorized officer, as the case may be, shall issue a refund adjustment order in Form VAT-25 authorizing him to deduct the amount refundable from the amount payable by him.



लगातार.....

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where a demand is outstanding against a dealer or a person who is entitled to a refund, the assessing authority or the authorized officer shall *suo motu* issue a refund adjustment order in Form VAT-25 for adjusting the refund against such outstanding demand.

(3) No claim of refund shall be rejected without giving the dealer or the person claiming refund, an opportunity of being heard and without recording reasons in writing.

12. वेट अधिनियम की धारा 17(2) के प्रावधानों की पालना में आयुक्त वाणिज्यिक कर राजस्थान के आदेश क्रमांक एफ.16(327)टैक्स/वैट/सीसीटी/06/1937 दिनांक 16.12.2006 के द्वारा स्टेनलेस स्टील पट्टा/पट्टी/शीट के विनिर्माताओं को समय से पूर्व प्रतिदाय का परिपत्र निम्नानुसार जारी किया गया है, जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने समय से पूर्व प्रतिदाय जारी किया है। परिपत्र निम्नानुसार है :-

No. F.16(327)Tax/VAT/06/1937

Dated 16.12.2006.

CIRCULAR

Sub.: Regarding early refunds to the manufacturers of stainless steel patta/ patti/ sheet.

Stainless steel flats are taxable at the rate of 4% in the State where the rate of CST on sale of stainless steel patta/ patti/ sheet manufactured for such flats is 0.50% under sub-section (5) of section 8 of CST Act, 1956. Major sales of stainless steel patta/ patti/ sheet takes place in the course of inter-State trade or commerce. In cases where the raw material is purchased from dealer registered in the State, the net tax payable by the manufacturer of stainless steel patta/ patti/ sheet has a negative value and such dealers are entitled to get refund of the excess amount paid on purchase of stainless steel flats. As per provisions of sub-section (2) of section 17 of the RVAT Act, 2003, ant refund has to be made only after the end of the immediately succeeding year, after first adjusting the same against ant tax payable or amount outstanding under the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) or under this Act or the repealed Act. However, the Commissioner, after recording reasons for doing so may, by a general or specific order, direct to grant such refunds even earlier.

The representative Association of the manufacturers of stainless steel patta/ patti/ sheet have requested for early refund as substantial amount of their working capital is blocked resulting in adverse impact on their business. Keeping in view the genuine hardship of the manufacturers of stainless steel patta/ patti/ sheet, it appears rational and appropriate that such dealers may be granted early refunds as per the provisions of sub-section (2) of section 17 of the Act. It is, therefore, Directed that where the



लगातार.....

net tax payable for any quarter has a negative value, the same shall be adjusted against any tax payable or amount outstanding under the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No.47 of 1956) or under this Act or any repealed Act, and the claimant registered dealer manufacturing stainless steel patta/patti/ sheet exclusively shall submit an application for early refund in Form- A appended hereunder, to the assessing authority for the remaining amount, along with the following documents:-

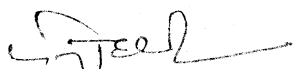
1. Copy of duly filled in Form VAT-07 in support of purchases against VAT invoices.
2. Duly filled in Form VAT-08.
3. In case genuineness of the purchase transactions in respect of which Input Tax Credit has been claimed is not proved and refund is found to be in excess of the refund due under the Act, with a view to make repayment of such refunded amount along with interest at the rate notified under section 55 of the RVAT Act, 2003, the applicant shall furnish security equal to the amount to be refunded, in any form as prescribed under Rule 77 of Rajasthan VAT Rules, 2006, To the satisfaction of the assessing authority.
4. Security shall not be demanded for the amount of refund where the deposit of tax on the transactions, on the basis of which refund has been claimed, is verified up to the first point in the series of sales. The assessing authorities shall record in writing the facts of such verification.
5. Certificate of Chartered Accountant as to the correctness of claim of refund in.

Form-B

The claim of concessional rate of tax will be limited to the extent of the declaration forms furnished by the dealer.

In view of the above, it is hereby directed that the assessing authorities, after having been satisfied with the genuineness of the transactions and the relevant document, shall dispose of the application of the stainless steel patta/ patti/ sheet manufactures claiming early refund within a period of thirty days from the date of submitting complete application in Form-A along with the above specified documents in the following manner:-

- (i) The assessing authority shall pass speaking order. Where refund is allowed partially or disallowed, the applicant shall be afforded opportunity of being heard before passing such order.
- (ii) Where the refund in part or in full is allowed, he shall issue refund order to the applicant in the manner specified under the Rajasthan VAT Rules, 2006.



लगातार.....

- (iii) Where the stainless steel patta / patti / sheet has been manufactured by the unit taken on rent/ lease, early refund shall be allowed to the extent of 75% of the refundable amount. However, refund of remaining amount of 25% shall be granted on furnishing of a bank guarantee valid for the period upto 31st March of the succeeding year, payable by a branch of a Nationalized Bank situated in the State.
- (iv) Subsequent to the passing of such order, if it is found that refund was granted in excess of the actual refund due, such excess refunded amount shall be recovered as if it is a tax levied from the dealer under this Act and the interest such tax shall be charged at the rate notified by the State Government under section 55 of the RVAT Act, 2003 for the period from the date of grant of refund, till the date such amount is paid in to Government treasury.
- (v) A separate register shall be maintained by each assessing authority for all the applications received for early refund and action taken thereon.

In case where refunds have been issued, the assessing authority should take steps on priority basis to finalize the pending assessments of such dealers, to verify transactions upto the first point in the series of sales on the basis of which refund has been claimed, to ensure actual deposit of tax of so refunded, and to get verified the declaration forms submitted by the dealer in support of concessional rate of tax.

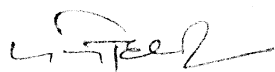
It should be ensured that no undue hardship is caused to the applicants and the applications are disposed of within the stipulated time. The Deputy Commissioner (Adm) shall monitor the cases of such refund. Additional Commissioners should also review a few cases of such refund during their visits to the offices.

13. इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी का प्रतिदाय जारी किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 21.7.2010 का सन्दर्भित पैरा निम्नानुसार है :-

“व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार इनपूट टैक्स क्रेडिट के जमा सत्यापन नहीं होने अथवा रिफण्ड से अधिक राशि का रिफण्ड होने की दशा में ब्याज सहित पुनः वसूली की जावेगी।

क्लैम किये गये इनपूट टैक्स क्रेडिट की गणना में अंतर्राष्ट्रीय विक्रय संव्यवहार में प्रस्तुत किये गये सी फार्म पर उपलब्ध रियायत को पश्चात् क्लैम की गयी रियायती दर की गणना की जांच में असत्य पाये जाने पर प्रत्यार्पण राशि मग ब्याज के नियमानुसार वसूली की जावेगी। वर्ष 2009-2010 के प्रथम त्रैमास 1.04.2009 से 30.06.2009 तक अवधि का नियमित करनिर्धारण आदेश अलग से पारित किया जावेगा।

प्रत्यार्पण आदेश रुपये 323165/- का जारी किया जाये।”



लगातार.....

14. हस्तगत प्रकरण अंतरिम आदेश के रूप में समयपूर्व प्रतिदाय देने पर पश्चात कर निर्धारण अधिकारी को यह समाधान होने पर कि प्रतिदाय चुकित है, अर्थात् जो राशि विधिक रूप से प्रतिदाय हेतु अनुज्ञेय से अधिक राशि जिसका कि वह हकदार नहीं है, प्रतिदाय हो चुके होने के कारण अविधिक रूप से हुए प्रतिदाय की बसूली का प्रकरण है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम अधीन किये गये अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किये गये विक्रय पर प्रस्ताव घोषणा-पत्र 'सी' में से कुछ घोषणा-पत्र 'सी' को अवैध घोषित किया। अधिसूचनायें निम्न प्रकार हैं :-

I, L. K. Giri, Joint Commissioner of Sales Tax, Registration Mumbai in exercise of the powers vested in me under sub-rule (4) of rule 4A of the Central Sales Tax (Bombay) Rules, 1957 hereby declare that the above declaration in Form 'C' bearing Sr. No. MH 09//1504628 to MH/09/364096, MH/09/960128 to MH/09/960138 and MH/09/1504616 to MH/09/1504628 (Forty-one declaration in 'C' Form) should be considered as invalid and cancelled ab in issue and shall not be used for the purpose of section 8(4) of the Central Sales Tax, 1956.

L. K. GIRI,

Joint Commissioner of Sales Tax
(Registration), Mumbai.

Mumbai,

Dated 31st January, 2011

I, L. K. Giri, Joint Commissioner of Sales Tax, Registration Mumbai in exercise of the powers vested in me under sub-rule (4) of rule 4A of the Central Sales Tax (Bombay) Rules, 1957 hereby declare that the above declaration in Form 'C' bearing Sr. No. MH 09/956387 to MH 09/956397, MH 09/1358021 to MH 09/1358023, MH 09/1355618 to MH 09/1655636 and MH 09/1612784 (Thirty four declaration in 'C' Form) should be considered as invalid and cancelled ab-in-issue and shall not be used for the purpose of section 8(4) of the Central Sales Tax, 1956.

L. K. GIRI,

Joint Commissioner of Sales Tax
(Registration), Mumbai.

Mumbai,

Dated 27th June, 2011

15. क्रेता व्यवहारी की राज्य सरकार द्वारा घोषणा-पत्रों को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(4) के प्रयोजनार्थ अवैध घोषित किया गया। महाराष्ट्र राज्य के क्रेता व्यवहारी ने कोई व्यापार नहीं करना घोषित किया। विक्रेता व्यवहारी द्वारा की गई बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(2) व 8(4) के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :-



लगातार.....

8. Rates of tax on sales in the course of inter-State trade commerce.-

- (1) Every dealer, who in the course of inter-State trade or commerce, sells to a registered dealer goods of the description referred to in sub-section (3), shall be liable to pay tax under the Act, which shall be three per cent, of his turnover or at the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate State under the sales tax law of that State whichever is lower: Provided that the Central Government may by notification in the Official Gazette, reduce the rate of tax under this sub-section.
- (2) The tax payable by any dealer on his turnover in so far as his turnover or any part thereof relates to the sale of goods in the course of inter-State trade or commerce not falling within sub-section (1), shall be at the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate State under the sales tax law of that State.

Explanation.— For the purposes of this sub-section, a dealer shall be deemed to be a dealer liable to pay tax under the sales tax law of the appropriate State, notwithstanding that he, in fact, may not be so liable under that law.

- (3) [The goods referred to in sub-section (1)
- (a) xxx
- (b) are goods of the class or classes specified in the certificate of registration of the registered dealer purchasing the goods, being intended for re-sale by him or subject to any rules made by the Central Government in this behalf, for use by him in the manufacture or processing of goods for sale or [in the tele-communications network or] in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power;
- (c) are containers or other materials specified in the certificate of registration of the registered dealer purchasing the goods, being containers or materials intended for being used for the packing of goods for sale;
- (d) are containers or other materials used for the packing of goods or classes of goods specified in the certificate of registration referred to in clause (b) or for the packing of goods in containers or other materials specified in the certificate of registration referred to in clause (c).

लगातार..... (1)

W. J. J.

- (4) The provisions of sub-section (1) shall not apply to any sale in the course of inter-State trade or commerce unless the dealer selling the goods furnishes to the prescribed authority in the prescribed manner a declaration duly filled and signed by the registered dealer to whom the goods are sold containing the prescribed particulars in a prescribed form obtained from the prescribed authority:

Provided that the declaration is furnished within the prescribed time or within such further time as that authority may, for sufficient cause, permit.];

- (5) Notwithstanding anything contained in this section, the State Government may [on the fulfilment of the requirements laid down in sub-section (4) by the dealer] if it is satisfied that it is necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Gazette subject to such conditions as may be specified therein direct :

(a) that no tax under this Act shall be payable by any dealer having his place of business in the State in respect of the sales by him, in the course of inter-State trade or commerce, to a registered dealer from any such place of business of any such goods or classes of goods as may be specified in the notification, or that the tax on such sales shall be calculated at such lower rates than those specified in sub-section (1) as may be mentioned in the notification;

(b) that in respect of all sales of goods or sales of such classes of goods as may be specified in the notification, which are made in the course of inter-State trade or commerce to a registered dealer by any dealer having his place of business in the State or by any class of such dealers as may be specified in the notification, or any person or to such class of persons as may be specified in the notification, no tax under this Act shall be payable or the tax on such sales shall be calculated at such lower rates than those specified in sub-section (1) as may be mentioned in the notification.

- (6) Notwithstanding anything contained in this section, no tax under the Act shall be payable by any dealer in respect of sale of any goods made by such dealer, in the course of inter-State trade or commerce to a registered dealer for the purpose of setting up, operation, maintenance, manufacture, trading, production, processing, assembling, repairing, reconditioning, re-engineering, packaging for use as packing material or packing accessories in a unit located in any special economic zone or for development, operation or maintenance of special economic zone by the developer of the special economic zone, if such registered dealer has been authorised



लगातार.....

to establish such unit or to develop, operate and maintain such special economic zone by the authority specified by the Central Government in this behalf.]

(7) The goods referred to in sub-section (6) shall be the goods of such class or classes of goods as specified in the certificate of registration of the registered dealer referred to in that sub-section.

(8) The provisions of sub-sections (6) and (7) shall not apply to any sale of goods made in the course of inter-State trade or commerce unless the dealer selling such goods furnishes to the authority referred to in sub-section (6) a declaration in the prescribed manner on the prescribed form obtained from the authority referred to in sub-section (5), duly filled in and signed by the registered dealer to whom such goods are sold.

Explanation.— For the purposes of sub-section (6), the expression “special economic zone” has the meaning assigned to it in clause (b) to Explanation 2 to the proviso to section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944).

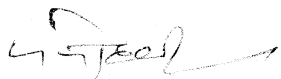
16. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन धारा 8(1) में रियायती कर दर के लिये धारा 8(4) की पालना अनिवार्य है। हस्तगत प्रकरण में क्रेता व्यवहार द्वारा महाराष्ट्र राज्य में कोई व्यापार करना घोषित नहीं करने के कारण उपरोक्त घोषणा-पत्र 'सी' को धारा 8(4) के प्रयोजनार्थ अवैध घोषित किया गया।

17. हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि क्या समयपूर्व दिये गए प्रतिदाय के सम्बन्ध में संव्यवहारों की जांच किये जाने पर क्रेता व्यवहारी महाराष्ट्र राज्य द्वारा अवैध घोषित घोषणा-पत्र 'सी' की बिक्री पर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) में विहित रियायती कर दर से करारोपण किया जायेगा तथा समयपूर्व दिया गया प्रतिदाय यथावत रहेगा अथवा नहीं ?

18. स्टेलनेस स्टील पट्टा/पट्टी पर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(5) के अधीन घोषणा-पत्र 'सी' प्रस्तुत करने की शर्त पर रियायती कर दर 0.5 प्रतिशत अधिसूचना क्रमांक 11-146 दिनांक 9.03.2011 से घोषित की गयी है।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गैसर्स इण्डिया एजेंसीज के मामले में दिये गये निर्णय, जो कि पैरा 8 में वर्णित है, में पैरा 15 में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि —

(i) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन घोषणा-पत्र 'सी' विहित करने का उद्देश्य यह है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में की गई बिक्री के विक्रेता राज्य जहां से वास्तव में बिक्री प्रभावित की गई है, विक्रेता व्यवहार द्वारा छिपाया नहीं जा सके तथा करारोपण नहीं किया जा सके; तथा

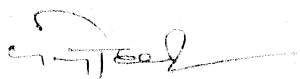


लगातार.....

(ii) साथ-साथ ही क्रेता व्यवहारी द्वारा भी उसके द्वारा की गई खरीद को नहीं छिपाया जा सके, क्योंकि क्रेता व्यवहारी के द्वारा विक्रेता व्यवहारी को 'सी' फॉर्म जारी कर दिये जाने के पश्चात् खरीद को नहीं छिपाया जा सकता है। घोषणा-पत्र जारी करने वाला क्रेता व्यवहारी जारी किये गये घोषणा-पत्र का विस्तृत लेखा सम्बन्धित राज्य के विभाग, जहां से घोषणा-पत्र प्राप्त किये गये हैं, को प्रस्तुत करेगा। क्रेता व्यवहारी घोषणा-पत्र 'सी' जारी करने से लाभान्वित होता है क्योंकि वह रियायती कर दर, जो भी विहित की गई है, को माल खरीदता है।

20. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय में दिये गये मत की पाठ्यता में यह निष्कर्षित किया जाता है कि प्रत्यर्थी विक्रेता व्यवहारी के द्वारा महाराष्ट्र राज्य के जिस क्रेता व्यवहारी को घोषणा-पत्र 'सी' के समर्थन पर रियायती कर दर से माल बेचना घोषित किया गया है तथा उस रियायती कर दर के आधारे पर लाभ उठाते हुए समयपूर्व प्रतिदाय भी प्राप्त कर लिया गया है। उक्त व्यवहारी द्वारा महाराष्ट्र राज्य में इस खरीद को घोषित नहीं किये जाने के कारण महाराष्ट्र राज्य के द्वारा क्रेता व्यवहारी के इन सन्दर्भित घोषणा-पत्रों को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(4) के प्रयोजनार्थ अवैध घोषित किये जाने के फलस्वरूप इस विक्रय के संव्यवहार पर धारा 8(1) के रियायती कर दर का प्रतिशत लागू की जाकर दिया गया प्रतिदाय विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को अधिनियम के अधीन देय प्रतिदाय का आधिक्य राशि का प्रतिदाय हो जाने के कारण प्रतिदाय का पुनर्भुगतान में ब्याज करने के लिये पारित आदेश में कोई त्रुटि किया जाना नहीं पाया जा सकता है। जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश अपारस्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

21. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा उद्धरित माननीय राजस्थान कर बोर्ड एकलपीठ के अपील संख्या 2288-2292/2012/जोधपुर एवं 262-263/2013/जोधपुर में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 18.03.2014 सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य यद्यपि हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के समानान्तर हैं किन्तु उक्त निर्णय से यह पीठ सहमत नहीं हैं क्योंकि माननीय एकलपीठ के निर्णय दिनांक 18.03.2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 139 एस.टी.सी. 329 (एस.सी.) इण्डिया एजेंसीज (रजि.) बनाम अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर बेंगलोर के सम्बन्ध में कोई विवेचन नहीं किया गया। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के पैरा 15 में दी गयी व्यवस्था के अनुसरण में प्रत्यर्थी को देय प्रतिदाय से अधिक राशि का प्रतिदाय




लगातार.....

हो जाने के कारण मय ब्याज के वसूलनीय है। अतः माननीय एकलपीठ का आदेश दिनांक 18.03.2014 प्रत्यर्थी व्यवहारी को कोई सहत प्रदान नहीं किया है।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त 139 एस.टी. 329 (एस.सी.) इण्डिया एजेंसीज (रजि) बन्नाम अतिरिक्त आसुक्त, वाणिज्यिक कर बेंगलोर के पैरा 15 में दी गयी व्यवस्था के प्रकाश में तथा सप्लायर विवेचना के आधार पर अपीलीय अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

23. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें स्वीकार कर जाकर, अपीलीय आदेश दिनांक 31.12.2012 को अपास्त किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी के पृथक-पृथक पारित किये गये आदेशों दिनांक 29.03.2012 को यथावत बहाल (restore) किया जाता है।

24. निर्णय सुनाया गया।


(नगोहर पुरा)
सादर